

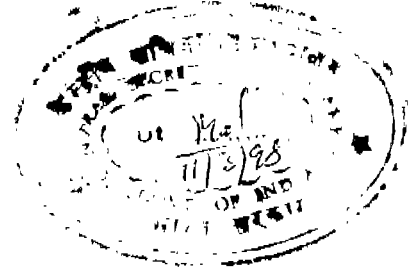


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 15]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 1998/पौष 29, 1919

No. 15]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 1998/PAUSA 29, 1919

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998

सा. का. नि.31 (अ):—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा 2 के खंड (ड) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण (अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है,

(ख) “अपील अधिकरण” से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित ऋण वसूली अपील अधिकरण अभिप्रेत है,

(ग) “पीठासीन अधिकारी” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(घ) “रिजर्व बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है,

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके समनुदिष्ट हैं।

3. अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्ति की पद्धति:—(1) पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति करने के परोक्ष के लिए एक संलग्न समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश,

- (ii) वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) में भारत सरकार का सचिव,
- (iii) विधि और न्याय मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव,
- (iv) रिजर्व बैंक का गवर्नर या रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक का उप गवर्नर,
- (v) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) में भारत सरकार का विशेष अपर/सचिव या बैंकिंग प्रभाग में विशेष अपर सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट बैंकिंग प्रभाग के संयुक्त सचिव या उस से उपर के बैंक का कोई अधिकारी,
- (2) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
- (3) समिति के किन्हीं तीन सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं, समिति की बैठक की गणपूर्ति करेंगे,
- (4) चयन समिति, पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी अभ्यर्थी का चयन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया बनाएगी।
- (5) चयन समिति, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए, विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात्, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची में व्यक्तियों में से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।
- (6) केन्द्रीय सरकार, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों की सूची बनाएगी और उक्त सूची दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार तैयार की गई सूची से की जाएगी।

4. चिकित्सक दृष्टया योग्यता—कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए गठित किए जाने वाले चिकित्सक बोर्ड द्वारा चिकित्सक दृष्टया योग्य घोषित नहीं किया जाता है या जब तक उसे समतुल्य प्राधिकरण द्वारा पहले ही योग्य घोषित नहीं किया गया है।

5. निर्वाचन:—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों में कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा के छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

7. पद और गोपनीयता की शपथ:—अधिनियम की धारा 9 के अधीन पीठासीन अधिकारी होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद को संभालने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्रारूपों में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा।

[फा. सं. 1/10/97-डी. आर. टी.]

डी. आर. एस. चौधरी, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

प्रारूप-I

(कृपया नियम 7 देखें)

(ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद की शपथ का प्रारूप)

मैं,.....(पीठासीन अधिकारी का नाम).....जो पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ मर्यादित से प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक और निष्ठापूर्वक, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का भय, अनुराग और द्वेष के बिना पालन करूंगा।

पीठासीन अधिकारी का नाम

ऋण वसूली अपील अधिकरण

प्रारूप-II

(कृपया नियम 7 देखें)

(ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा गोपनीयता की शपथ का प्रारूप)

मैं,.....(पीठासीन अधिकारी का नाम).....जो पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त

हुआ हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, कि मैं किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को कोई ऐसा विषय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा, जो उक्त ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे विचाराधीन लाया जाएगा या मेरी जानकारी में लाया जाएगा, सिवाय उनके जो पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अपेक्षित हैं।''

पीठासीन अधिकारी का नाम
ऋण वसूली अपील अधिकरण

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1998

G.S.R. 31(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 read with clause (e) of sub Section 2 of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Appellate Tribunal) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);

(b) "Appellate Tribunal" means the Debts Recovery Appellate Tribunal established under section 8 of the Act;

(c) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of an Appellate Tribunal under section 9 of the Act;

(d) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(e) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Method of appointment under section 9 of the Act.— (1) For the purpose of appointment to the post of a Presiding Officer, there shall be a Selection Committee consisting of—

(i) The Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India.

(ii) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs);

(iii) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Law and Justice;

(iv) the Governor, of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank nominated by the Governor of the Reserve Bank;

(v) an special Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division) or an officer not below the rank of Joint Secretary in the Banking Division nominated by the special Additional Secretary in the Banking Division.

(2) The Chief Justice of India the Judge of the Supreme Court shall be the Chairman of the Selection Committee.

(3) Any three members of the Committee including the Chairman shall form a quorum for meeting of the Committee.

(4) The Selection Committee may devise its own procedure for selecting a candidate for appointment as Presiding Officer

(5) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as Presiding Officer from amongst the persons on the list of candidates prepared by the Ministry of Finance after inviting applications therefor by advertisement.

(6) The Central Government shall on the basis of the recommendations of the Selection Committee make a list of persons selected for appointment as Presiding Officer and the said list shall be valid for a period of two years. The appointment of a Presiding Officer shall be made from the list so prepared.

4. Medical Fitness.— No person shall be appointed as a Presiding Officer unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

5. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules the same shall be referred to the Central Government for its decision.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Oaths of office and secrecy - Every person appointed to be Presiding Officer under section 9 of the Act shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Forms annexed to these rules.

[F.No. 1/10/97-DRT.]

D R.S. CHAUDHARY, Jt. Secy.

ANNEXURE

FORM-I

(See Rule 7)

Form of oath of office for Presiding Officer of the Debts Recovery
Appellate Tribunal.

"I, (Name of the Presiding Officer), having been appointed as Presiding Officer do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Presiding Officer to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill will.

**NAME OF THE PRESIDING OFFICER
DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL**

FORM - II

(See rule 7)

Form of oath of secrecy for Presiding Officer of the Debts Recovery
Appellate Tribunal.

"I, (Name of the Presiding Officer), having been appointed as Presiding Officer do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Presiding Officer of said Debts Recovery Appellate Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as the Presiding Officer "

**NAME OF THE PRESIDING OFFICER
DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL**

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998

सा. का. नि. 32 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा 2 के खंड (ड) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है,

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अधिकरण अभिप्रेत है,

- (ग) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
- (घ) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है,
- (ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें समनुदिष्ट हैं।

3. अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन नियुक्ति की पद्धति—(1) पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश,
- (ii) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में भारत सरकार का सचिव,
- (iii) विधि और न्याय मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव,
- (iv) रिजर्व बैंक का गवर्नर या रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक का उप गवर्नर,
- (v) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) में भारत सरकार का विशेष/विशेष सचिव या उस अपर सचिव या बैंकिंग प्रभाग में अपर सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट बैंकिंग प्रभाग के संयुक्त से उपर के बैंक का कोई अधिकारी,
- (2) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
- (3) समिति के किन्हीं तीन सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं, समिति की बैठक की गणपूर्ति करेंगे,
- (4) चयन समिति, पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी अभ्यर्थी का चयन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया बनाएगी
- (5) चयन समिति, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए, विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात्, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची में व्यक्तियों में से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।
- (6) केन्द्रीय सरकार, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों की सूची बनाएगी और उक्त सूची दो वर्ष की अवधि के लिए विधिवान्वित होगी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार तैयार की गई सूची से की जाएगी।

4. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता—कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए गठित किए जाने वाले चिकित्सक बोर्ड द्वारा चिकित्सक दृष्ट्या योग्य घोषित नहीं किया जाता है या जब तक उसे समस्तुल्य प्राधिकरण द्वारा पहले ही योग्य घोषित नहीं किया गया है।

5. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों में कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा के छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

7. पद और गोपनीयता की शपथ—अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन पीठासीन अधिकारी होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद को संभालने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्रारूपों में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा।

[फा. सं. 1/10/97-डी. आर. टी.]

डी. आर. एस. चौधरी, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

प्रारूप-I

(कृपया नियम 7 देखें)

ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन

अधिकारी के पद की शपथ का प्रारूप

मैं.....(पीठासीन अधिकारी का नाम).....जो पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक और निष्ठापूर्वक, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का भय, अनुराग और द्वेष के बिना पालन करूंगा।"

पीठासीन अधिकारी का नाम

ऋण वसूली अधिकरण

प्ररूप-II

(कृपया नियम 7 देखें)

ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन

(अधिकारी द्वारा गोपनीयता की शपथ का प्ररूप)

मैं, (पीठासीन अधिकारी का नाम), जो पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, कि मैं किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को कोई ऐसा विषय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा, जो उक्त ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे विचाराधीन लाया जाएगा या मेरी जानकारी में लाया जाएगा, सिवाय उनके जो पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अपेक्षित हैं।"

पीठासीन अधिकारी का नाम

ऋण वसूली अधिकरण

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1998

G.S.R. 32(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with clause (e) of sub-section 2 of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);

(b) "Tribunal" means the Debts Recovery Tribunal established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of a Tribunal under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(d) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(e) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Method of appointment under sub-section (1) of section 4 of the Act.— (1) For the purpose of appointment to the post of a Presiding Officer, there shall be a Selection Committee consisting of —

(i) The Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India;

(ii) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs);

(iii) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Law and Justice;

(iv) the Governor, of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank nominated by the Government of the Reserve Bank;

(v) Special Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) or an officer not below the rank of Joint Secretary in the Banking Division nominated by the special Additional Secretary in the Banking Division.

(2) The Chief Justice of India or the Judge of the Supreme Court shall be the Chairman of the Selection Committee.

(3) Any three members of the Committee including the Chairman shall form a quorum for meeting of the Committee.

(4) The Selection Committee may devise its own procedure for selecting a candidate for appointment as Presiding Officer.

(5) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as Presiding Officer from amongst the persons on the list of candidates prepared by the Ministry of Finance after inviting applications therefor by advertisement.

(6) The Central Government shall on the basis of the recommendations of the Selection Committee make a list of persons selected for appointment as Presiding Officer and the said list shall be valid for a period of two years. The appointment of a Presiding Officer shall be made from the list so prepared.

4. Medical Fitness.— No person shall be appointed as a Presiding Officer unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

5. Interpretation.— If any question arises relating to the interpretation of these rules the same shall be referred to the Central Government for its decision.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Oaths of office and secrecy.— Every person appointed to be Presiding Officer under sub section (1) of the section 4 shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Forms annexed to these rules.

[F.No. 1/10/97-DRT.]

D. R. S. CHAUDHARY, Jt. Secy.

FORM-I

(See Rule 7)

Form of oath of office for Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal.

"I.....(Name of the Presiding Officer) having been appointed as Presiding Officer do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Presiding Officer to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill will.

**NAME OF THE PRESIDING OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**

FORM - II

(See rule 7)

Form of oath of secrecy for Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal.

"I, (Name of the Presiding Officer) having been appointed as Presiding Officer do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Presiding Officer of said Debts Recovery Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as the Presiding Officer."

**NAME OF THE PRESIDING OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**

